

विनोद अडाणी पर आरोप साबित नहीं कर सका सेबी

► सेबी ने बंद की कार्रवाई

नवभारत न्यूज मुंबई, 30 सितंबर. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि वह अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और 11 अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) तथा शेयरधारिता के आरोपों को आगे नहीं बढ़ाएगा.

सेबी के 23 सितंबर के अंतिम आदेश में कहा गया है कि बाजार नियामक यह साबित नहीं कर सका कि विनोद अडाणी या समूह की चार कंपनियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो

गौतम अडाणी का मामला सेबी के साथ निपटा



लिमिटेड, अडाणी पावर लिमिटेड, अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (अडाणी एपीएसईजेड) के अलावा अन्य निदेशक और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं. यह मामला जून और जुलाई 2020 में सेबी को मिली शिकायतों से जुड़ा है.

निवेशकों का कंपनियों पर नियंत्रण था. इस 81 पृष्ठ के अंतिम आदेश में सेबी ने कहा कि उसकी जांच यह साबित करने में विफल रही कि विनोद अडाणी ने

दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स (ईआईएफएफ) और ईएम रिस्ट्रेट फंड (ईएमआर) के निवेश संबंधी फैसलों का

निर्देश दिया था या ओपल इन्वेस्टर्स के अडाणी पावर लिमिटेड में निवेश को नियंत्रित किया था.बाजार नियामक ने कहा कि यह आरोप नहीं था कि विनोद अडाणी या प्रवर्तक समूह दो एफपीआई या ओपल के नाम पर रखे गए शेयरों के वास्तविक लाभार्थी मालिक थे.

आरोप यह था कि विनोद अडाणी ने निवेश संबंधी फैसलों का निर्देश देकर उन शेयरों को नियंत्रित किया. नियामक को इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला कि विनोद अडाणी ने नाफिर अली शाहन अडाणी या चांग चुंग-लिंग को नियंत्रित किया और उनके जरिए अडाणी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले संबंधित निवेशकों के फैसलों को प्रभावित किया.



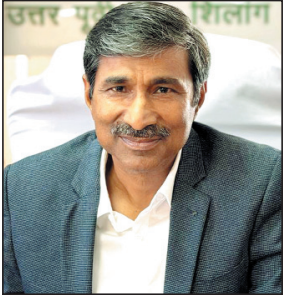
नियंत्रण साबित करने साक्ष्य जरूरी

सेबी ने कहा कि हालांकि, वास्तविक नियंत्रण साबित करने के लिए ऐसे साक्ष्य जरूरी हैं, जिनसे यह पता चले कि कोई व्यक्ति प्रवर्तन या नीतिगत फैसलों का प्रत्यक्ष रूप से निर्देश देता है. इसे केवल संबंध या कारोबारी अथवा वित्तीय संबंधों के आधार पर नहीं माना जा सकता. आदेश में कहा गया है कि कारोबारी या वित्तीय संबंधों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि विनोद अडाणी इन सभी पर नियंत्रण रखते हैं.

पावरग्रिड के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र प्रमुख बने धर्मबीर कुमार

नवभारत कनेक्ट गुवाहाटी, 30 सितंबर. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) के कार्यपालक निदेशक धर्मबीर कुमार ने 18 सितंबर 2026 से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली (एनईआरटीएस) के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है.

जुलाई में कार्यपालक निदेशक पद पर पदोन्नत किए गए कुमार को विद्युत पारेषण क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. पावरग्रिड में करीब साढ़े तीन दशक के सेवाकाल के दौरान उन्होंने पारेषण परियोजनाओं से लेकर उपकेंद्रों के संचालन और



अनुरक्षण तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है.

धर्मबीर कुमार ने जनवरी 1994 में पावरग्रिड के साथ अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने वर्ष 1992 में बी. आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय,

मुजफ्फरपुर से विद्युत अभियांत्रिकी में बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की. कंपनी में लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर-पूर्वी एवं पूर्वी क्षेत्रों के अलावा कॉरपोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां संभालीं.

उनके कार्य अनुभव में उपकेंद्र अनुरक्षण, संचालन एवं अनुरक्षण, परामर्श, पारेषण लाइन एवं उपकेंद्र परियोजनाएं तथा परियोजना निष्पादन प्रमुख रूप से शामिल हैं. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से उनका पुराना कार्य अनुभव भी रहा है. उन्होंने जीरिबाम और सेप्पा में सेवाएं दी हैं.

सेबी ने ग्रीफिटल पर कसा शिकंजा

- खेती में 18.5% टैक्स-फ्री मुनाफे का झांसा
- 192.88 करोड़ लौटाने का आदेश

नवभारत न्यूज नेटवर्क मुंबई, 30 सितंबर. खेती में निवेश कर मोटा और टैक्स-फ्री मुनाफा कमाने का सपना दिखाने वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्रीफिटल पर बाजार नियामक सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है.

सेबी ने बिना वैध पंजीकरण के सामूहिक निवेश योजना चलाने के मामले में ग्रीफिटल और उससे जुड़ी 28 इकाइयों पर 25 करोड़

रुपये से ज्यादा की पेनल्टी लगाई है. साथ ही 5,208 निवेशकों से जुटाए गए 192.88 करोड़ रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया है. सेबी के रिकॉर्ड में 28 सितंबर 2026 को ग्रीफिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा अंतिम आदेश दर्ज है. ग्रीफिटल ने कृषि में निवेश के नाम पर आम लोगों को 18.5 प्रतिशत तक टैक्स-फ्री मुनाफे का भरोसा दिया था. प्लेटफॉर्म ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2024 के बीच निवेशकों से पैसा जुटाया. इसके लिए कुल 18 योजनाएं पेश की गईं और निवेश की न्यूनतम रकम 5,000 रुपये रखी गई थी.

आज से बदलेंगे गैस और एफडी के कई नियम



नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. आज से रसोई गैस की सब्सिडी, बैंक की बड़ी संपाधि जमा और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान लागू होंगे. नए नियमों का असर अलग-अलग वर्ग के लोगों पर अलग तरीके से पड़ेगा.

जहां एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वहीं बड़ी रकम

संपाधि जमा करने वाले ग्राहकों के लिए बैंकिंग नियमों में बदलाव होगा. आज से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा. जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इसे पूरा करना होगा. हालांकि, प्रमाणीकरण नहीं कराने पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद नहीं होगी. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी. भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रावधानों के अनुसार अब 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपाधि जमा को बड़ी जमा माना जाएगा. बैंकों को ऐसी जमा की ब्याज दरों को लेकर निर्धारित पारदर्शिता नियमों का पालन करना होगा.

भारत में लॉन्च हुआ एपल पे

- अब आई फोन से होगा सुरक्षित भुगतान
- दुकानों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक कर सकेंगे भुगतान



नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. एपल ने भारत में अपनी डिजिटल भुगतान सेवा एपल पे शुरू कर दी है. अब आईफोन, आईपैड और एपल वॉच इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अपने पात्र क्रेडिट कार्ड को एपल वॉलेट में जोड़कर दुकानों, ऐप और वेबसाइट पर भुगतान कर सकेंगे.

शुरुआत में एपल पे के लिए एक्सिस बैंक द्वारा जारी वॉजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं. मैक कंप्यूटर के लिए एपल पे

की सुविधा बाद में शुरू की जाएगी.

एपल पे के जरिए भुगतान करते समय कार्ड की जानकारी बार-बार दर्ज करने, व्यक्तिगत पहचान संख्या या एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड

डालने की जरूरत नहीं होगी. दुकान पर आईफोन से भुगतान करने के लिए साइड बटन या होम बटन को दो बार दबाकर चेहरे की पहचान, स्पर्श पहचान या उपकरण के पासकोड से सत्यापन करना होगा.

इसके बाद फोन के ऊपरी हिस्से को संपर्क रहित भुगतान मशीन के पास ले जाकर भुगतान किया जा सकेगा. एपल वॉच से भी इसी तरह भुगतान किया जा सकेगा. ग्राहक नवीनतम एक्सिस बैंक ऐप के जरिए कार्ड को सीधे एपल वॉलेट में जोड़ सकते हैं.

कंपनी के मुताबिक वास्तविक कार्ड संख्या न तो उपकरण में सामान्य रूप से सुरक्षित रखी जाती है और न ही एपल के सर्वर पर. भुगतान के दौरान यह जानकारी दुकानदार के साथ भी साझा नहीं होती. इसके बजाय प्रत्येक उपकरण के लिए एक विशिष्ट खाता संख्या बनाई जाती है, जिसे उपकरण की सुरक्षित चिप में कूटबद्ध रूप से सुरक्षित रखा जाता है.

जियो ने जोड़े 24 लाख ग्राहक

► एयरटेल से जुड़े 21.1 लाख कनेक्शन



सक्रिय ग्राहकों में एयरटेल अब्बल- टेलीकॉम रजिस्टर के

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के टेलीकॉम सेक्टर में अगस्त महीने के दौरान मजबूत बढ़त दर्ज की गई है. रिलायंस जियो ने बाजार में अपना दबदबा कायम रखते हुए सबसे अधिक नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं, जबकि भारतीय एयरटेल भी दूसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है.

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में निजी कंपनियों का दबदबा बरकरार रहा, जबकि सरकारी कंपनियों में मिला-जुला रझान देखने को मिला.

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का दायरा भारत में अब तक मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को मिलाकर देश में कुल वायरलेस ग्राहकों की संख्या बढ़कर 131.22 करोड़ पहुंच गई, जो जुलाई की तुलना में 0.46% की मासिक वृद्धि दर्शाती है.

शहरी ग्राहक: जुलाई के 75.38 करोड़ से बढ़कर अगस्त में 75.91 करोड़ हुए.

ग्रामीण ग्राहक: जुलाई के 55.24 करोड़ से बढ़कर अगस्त में 55.31 करोड़ हुए.

बाजार हिस्सेदारी: निजी दूरसंचार कंपनियों की कुल वायरलेस बाजार में 92.75% हिस्सेदारी रही, जबकि सरकारी कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी 7.25% रह गई.

आरबीआई बढ़ा सकता है ब्याज दरें



2 अक्टूबर को नो यूपीआई डे का ऐलान

एमडीआर के विरोध में मोबाइल व्यापारी

ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गांधी जयंती के दिन दुकानदार सांकेतिक विरोध के

तौर पर अपने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढकेंगे और यूपीआई से भुगतान नहीं लेंगे.

एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम यूपीआई या डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं, बल्कि छोटे दुकानदारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के विरोध में है. एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को भेजे ज्ञापन में यूपीआई मर्चेंट भुगतान को पहले की तरह जीरो एमडीआर रखने की मांग की है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अक्टूबर और दिसंबर की नीति समीक्षा बैठकों में ब्याज दरें 25 आधार अंक बढ़ा सकता है. इससे टर्मिनल दर 5.75 फीसदी तक पहुंच जाएगी.

प्रदूषण घटाने की योजना में एलएनजी वाहन भी होंगे शामिल

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. प्रदूषण कम करने और पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों से बदलने की केंद्र सरकार की योजना का दायरा बढ़ सकता है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहनों के साथ अब तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी से चलने वाली बसों और ट्रकों को भी योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाकर एलएनजी से चलने वाले नए वाहन खरीदने वाले संचालकों को भी योजना के तहत प्रोत्साहन मिल सकता है. प्रस्तावित बदलाव का सीधा संबंध परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करने से है. पुराने वाणिज्यिक वाहन अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं. ऐसे वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर कम प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से इलेक्ट्रिक और सीएनजी विकल्पों पर जोर दे रही है. अब एलएनजी को भी इसी दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है.

समाचार विशेष

यूपी कांग्रेस प्रभारी के दावे से गरमाई सियासत

► सीट-शेयरिंग पर कहा- 150 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे चुनाव

लखनऊ, 30 सितंबर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बीच यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पार्टी 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी.

उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट-शेयरिंग पर अक्टूबर में अंतिम फैसला होने की संभावना है. कांग्रेस के पास राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं. राज्य प्रभारी ने जोर देकर कहा कि गठबंधन के

तहत कांग्रेस पार्टी 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी. गौतम ने कहा, सीट-शेयरिंग पर अक्टूबर महीने में अंतिम फैसला होने की संभावना है. आगे कहा कि गठबंधन के तहत, कांग्रेस पार्टी 50 प्रतिशत सीटें पाने की हकदार है.

कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी. उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों से कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में सीट-शेयरिंग पर काम कर रही है. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और

मैं इस काम को देख रहे हैं. राज्य प्रभारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के मुख्य सहयोगी हैं. इन दोनों पार्टियों ने राज्य में 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ा था.

इधर बीजेपी बना रही रणनीति

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति बनाने और संगठनात्मक तैयारी को मजबूत करने के मकसद से 3 और 4 अक्टूबर को मथुरा में दो दिन की संगठनात्मक बैठक करेगी. ब्रज क्षेत्र में होने वाली इस अहम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी करेंगे. बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है. इस बैठक में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है. दो दिन की इस बैठक में ब्रज क्षेत्र में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति, जमीनी स्तर पर तैयारियों और पार्टी के राज्य व क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के उपायों पर

वेकोलि मुख्यालय में राजभाषा पखवाड़े का समापन

12 से अधिक प्रतियोगिताओं में 300 से ज्यादा कार्मिकों ने लिया हिस्सा

नवभारत कनेक्ट

नागपुर, 30 सितंबर. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) मुख्यालय में 15 से 29 सितंबर तक आयोजित राजभाषा पखवाड़ा-2026 का मंगलवार को सांस्कृतिक भवन, कोयला विहार कॉलोनी में समापन हुआ.

समारोह में वर्षभर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों और क्षेत्रों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कुल 107 पुरस्कार प्रदान किए गए. कार्यक्रम की अध्यक्षता वेकोलि के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. हेमंत शर्मा पांडे ने की. पखवाड़े के दौरान हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए 12 से अधिक प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया. इनमें चित्र आधारित कहानी लेखन, सामान्य ज्ञान, तात्कालिक भाषण, अंताक्षरी, प्रश्न मंच, स्व-रचित



काव्य पाठ और टिप्पण एवं आलेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं. मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान' पर आधारित 'पढ़ो किताब, दो जवाब' प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. कार्मिकों के बच्चों के लिए हिंदी स्लोगन एवं चित्रकला तथा विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी हुई. आयोजनों में 300 से

अधिक कार्मिकों ने भाग लिया, जबकि भारती कृष्ण विद्या विहार विद्यालय के विशेष कार्यक्रम में करीब 500 विद्यार्थी शामिल हुए. हिंदी संवर्ग के कर्मियों के लिए 24 सितंबर को इंदौर परिसर में विशेष राजभाषा कार्यशाला भी आयोजित की गई. इस वर्ष 'प्रश्न मंच' प्रतियोगिता पहली बार मुख्यालय भवन के विभिन्न तलों की 12

सपा-कांग्रेस में मुस्लिम वोट की खींचतान

लखनऊ, 30 सितंबर. वैसे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मन में कोई भ्रम नहीं है. वे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सपा ही इस बार भाजपा से लड़ने वाली मुख्य ताकत है. पिछले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने देखा कि भाजपा के समर्थक मतदाताओं में भी अगर भाजपा से नाराजगी होती है तो वे भाजपा को हराने के लिए सपा के साथ जाते हैं. संविधान और आरक्षण पर खतरे से जो वर्ग नाराज हुआ वह भाजपा को हराने के लिए सपा के साथ गया और तभी लोकसभा में सपा 37 सीट जीत

कर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी. उसके साथ तालमेल का फायदा कांग्रेस को भी हुआ.

सो, मुस्लिम मतदाताओं के मन में कोई भ्रम नहीं है. फिर भी कांग्रेस के नेता इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी के मन में यह आशंका पैदा की जाए कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ जा सकता है.

इसका मकसद दबाव बना कर विधानसभा की ज्यादा सीटें हासिल करना है. हालांकि सपा को हकीकत पता है. जब लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उसके साथ आया तो विधानसभा चुनाव

में कांग्रेस के साथ क्यों जाएगा. इसके बावजूद सपा भी इस खेल में शामिल है. सपा ने पिछले दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद को अपनी पार्टी में शामिल कराया. इसके जवाब में कांग्रेस ने बसपा और एमआईएम के कई मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है. एमआईएम के मुखर नेता आसिम वकार पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए. अब बसपा सरकार में मंत्री रहे इजहारूल हक और 2024 में बसपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े नईम अहमद को पार्टी में शामिल कराया.

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम-नगम) सीआईएन.नं. - एल748999डीएलआई999जीओआई101707		
खुली ई-निविदा आमंत्रण सूचना आईआरसीटीसी-पश्चिम क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित खुली ई-निविदा (दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से) आमंत्रित की जाती है:-		
इकाई	विवरण	साइट पर निविदा दस्तावेज की उपलब्धता
फ्रिजशमेंट रूम, जन आहार, फूड प्लाइव एवं फास्ट फूड इकाई	पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत दौंड, भोपाल, बीना, इटारसी, सुर्देनगर, शेराव और अकोला के जलपान कक्षों में खानपान सेवाएं उपलब्ध कराने तथा पिपरिया और रत्नाम में जन आहार, मणिंगार में एफपी, समीक्याली और तलेगांव रेलवे स्टेशनों पर एफएमयू के लिए खुली ई-निविदा सह नीलामी	01/10/2026 से 12:00 बजे से
निविदा दस्तावेज डाउनलोड एवं भागीदारी वेबसाइट :- www.tenderwizar.com/IRCTC पर की जा सकती है। उपरोक्त विधानपत्र के संबंध में कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी किए जाने की स्थिति में इसे केवल वेबसाइट www.irctc.com और www.tenderwizar.com/IRCTC पर प्रकाशित किया जाएगा। कार्यालय का पता:- जीजीएम, पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, तल मंजिल, फोर्ब्स बिल्डिंग, चरनजीव राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001. दूरभाष:- 022-47509565/8815		
अपने भोजन की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए कृपया www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या "फूड अट्रैक्ट" मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.		